खेती की घटती प्रासंगिकता के कारण और निवारण

* डॉ. माधवी दुबे

भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहां की 68% जनसंख्या प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। पिछले कुछ दशकों से खेती लाभ का व्यवसाय रहा है और तेजी से सामाजिक असमानता में वृद्धि हुई है। यद्यपि भारत के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है लेकिन भारतीय कृषक संरचना को तथ्यात्मक आधार पर विश्लेषण करने पर ज्ञात होता है –

देश में 12% सीमांत कृषक (1 हेक्टेयर से कम) 14% लघु किसान (2 हेक्टेयर तक की भूमि), 21% अर्द्धमध्यम (2–4 हेक्टेयर भूमि वाले), 30% मध्यम (4–5 हेक्टेयर भूमि वाले), 23% बड़ी जोत (10 हेक्टेयर से अधिक वाले) किसान में खेतीहर मजदूर सीमांत किसान एवं छोटे किसान मिलाकर कुल ग्रामीण परिवारों के 72.2% की भाग का निर्माण करते है। पिछले 10 वर्षों के दौरान गाँव की 27% कृषि भूमि घटी है और गैर किसानीकरण की समस्या उत्पन्न हुई है। बेरोजगारी, कुपोषण, निरक्षरता संसाधनों के अभाव से युक्त बहुसंख्यक आमकृषक वर्तमान दौर में खेती को प्राथमिक व्यवसाय के रूप में अपनाने से कतरा रहा है। NSS के हाल में दिये तथ्यों के आधार पर स्पष्ट होता है कि देश के 40% किसान खेती छोड़ने की इच्छा रखते हैं जबकि 50% किसान कर्ज में डूबे हैं 6.4 लाख गांवों से युक्त भारतीय ग्रामीण संरचना में आधारभूत संरचना (बिजली, सड़क, संचार) स्वास्थ्य, शिक्षा लिंगभेद की दृष्टि से बेहद असमान है अर्थात् एक ओर हेल्थटूरिज्म भारत का बड़ा उद्योग है। विदेशी नागरिक बड़ी संख्या में सस्ता इलाज कराने इंडिया आते हैं। वहीं मलेरिया जैसी छोटी बीमारी प्रसव के दौरान मातृ मृत्यु की संख्या कम नहीं है। 6–14 वर्ष की उम्र के सभी बच्चों को स्कूल में दाखिला नहीं दिला पाते हैं। महिला विकास सूचकांक में भारत 157 देशों में 113 वें स्थान पर है। सामाजिक असमानता में वृद्धि के साथ कृशि जो भारत का मुख्य व्यवसाय है सकल घरेलू उत्पाद में योगदान घटता जा रहा है। प्रथम योजना काल में सकल घरेलू उत्पाद में कृशि का योगदान 52.2%था जो 2006–07 में 17.5% रह गया है। पिछले डेढ़ दशक में समूचे देश में लगभग एक लाख किसान आत्महत्या कर चुके हैं। विश्व व्यापार संगठन की शर्तों के अनुरूप संविदा खेती, टर्मिनेशन बीज, सबसिडी में कमी, कृषि इनपुट्स (बिजली, पानी, खाद, कीटनाशक, यातायात आदि) में मूल्य वृद्धि हुई है। इस तरह कृषि का विकास पिछड़ रहा है और बदलती हुई इन परिस्थितियों में गैर किसानीकरण (Problem of De-Agrinization) की समस्या विकसित हो रही है।

उल्लेखनीय है कि आधुनिक उद्योग रोजगार रहित विकास को प्रोत्साहित करते हैं जबकि कृषि रोजगारपरक विकास (फसल, पशुपालन, मत्स्यपालन, वानिकी, खाद्य प्रसंस्करण) को प्रोत्साहित करती है लेकिन अकुशल मानवीय संसाधन, न तो औद्योगिक क्षेत्र में उच्च स्तर के अवसर प्राप्त कर पा रहा है और न ही कृषि में नवाचारों का उपयोग कर पा रहा है। इस तरह बढ़ती हुई जनसंख्या और औद्योगिक क्षेत्र की अपेक्षाकृत धीमी विकास गति के कारण ग्रामीण क्षेत्र में प्रत्यक्ष और परोक्ष बेरोजगारी में लगातार वृद्धि हुई है। भूमि पर जनसंख्या का दबाव बढ़ने से पिछले 10 वर्षों में गांव की 27 प्रतिशत कृषि भूमि घटी है। खेती पर श्रम करने वाले वर्ग में पलायन की प्रवृत्ति बढ़ी है।

प्रस्तुत शोध पत्र में म.प्र. नरसिंहपुर जिले के 265 किसानों पर कृषि कार्य में संलग्नता व भविष्य में कृषि को अपनाये जाने के रूझान से संबंधित अध्ययन किया गया है। म.प्र. का नरसिंहपुर जिला कृषि प्रधान जिला है जहां रबी, खरीफ फसलें, गन्ना आदि का उत्पादन प्रचुर मात्रा में होता है। अतः हमने इस क्षेत्र का चयन किया।

अध्ययन का उद्देश्य–निम्नलिखित प्राकल्पनाओं की जांच करना अध्ययन का उद्देश्य है –

1. परम्परागत कृषि के स्थान पर हरितक्रान्ति के परिणामस्वरूप खेती में उत्पादन तो बढ़ा है पर गुणवत्ता में वृद्धि नहीं हुई।
2. सीमान्त कृषकों की पहुंच शासन द्वारा निर्धारित सुविधाओं को प्राप्त करने में व संसाधनों तक पहुंच में सीमित है।
3. खाद्य प्रसंस्करण, विपणन आदि की सुविधाओं का अभाव होने के कारण कृषि उत्पादन का समुचित लाभ नहीं मिल पा रहा है।
4. कृषि में नवाचारों का प्रयोग सीमित मात्रा में हुआ है व आधारभूत संरचना के साथ ही सामाजिक संरचना में असंतुलित विकास की स्थिति विद्यमान है।
5. उदारीकृत अर्थव्यवस्था में भारतीय कृषकों की समस्याएं बढ़ी हैं।
6. उपभोक्तावादी प्रवृत्ति व आधुनिकता के आकर्षण में कृषि और कृषि से जुड़े कार्य महत्वहीन होते जा रहे हैं।

अध्ययन पद्धति

प्रस्तुत शोध कार्य हेतु साक्षात्कार पद्धति के माध्यम से तथ्यों का संकलन किया गया है।

तथ्यात्मक विश्लेषण

अध्ययन हेतु 265 कृषकों को निदर्श के रूप में लिया, संबंधित कृषकों से कृषि के प्रति उनके रूझान को समग्रता से जानने का प्रयास किया गया है।

तालिका–1

आयु समूह के आधार पर निदर्श का वर्गीकरण

आयु समूह	कृषक संख्या	प्रतिशत
20–25	14	5.30
26–50	156	58.80
50 से अधिक	95	35.90

तालिका–2

शिक्षा के आधार पर निदर्श का वर्गीकरण

शिक्षा का स्तर	कृषकों की संख्या	प्रतिशत
अशिक्षित	101	38.10
प्रायमरी	94	35.5
हाई स्कूल	65	24.5
उच्च शिक्षा स्नातक	5	1.90
योग	265	100

तालिका–3

निदर्श का कार्य (व्यवसाय) के आधार पर वर्गीकरण

व्यवसाय	कृषकों की संख्या	प्रतिशत
कृषि	182	68.70
कृषि और शासकीय/ अशासकीय नौकरी	29	10.90
कृषि और अन्य कार्य	54	20.40
योग	265	100

* एफ–85/22, तुलसी नगर, भोपाल

तालिका–4
जाति के आधार पर निदर्श का वर्गीकरण

जाति	कृषकों की संख्या	प्रतिशत
अनुसूचित जाति	65	24.50
अनु. जनजनजाति	10	3.80
अन्य पिछड़ा वर्ग	34	12.80
सामान्य	156	58.90

तालिका–5
कृशि भूमि स्वामित्व के आधार पर निदर्श का वर्गीकरण

जोत का आकार	कृषकों की संख्या	औसत भूमि
का आकार (हेक्टेयर)		
छोटे व सीमांत कृषक	140	
(52.80 प्रतिशत)	1.72	
मध्यम जोत	95	
(35.90 प्रतिशत)	6.23	
बड़े जोत वाले कृषक	30	
(11.30 प्रतिशत)	20.59	

तालिका–6
कृषि मैं नवाचारों का प्रयोग करते हैं।

कृषक	करते हैं	नहीं करते आंशिक रूप
मैं करते हैं।	योग	
छोटे व सीमांत	–	140
(52.80%)	–	140
मध्यम	60	
(36.10 %)	–	35
(13.30%)	95	
बड़े जोत वाले	30	(11.30 %)
–	–	30

तालिका–7
निदर्श के ऋण प्राप्ति के स्रोत

स्त्रोत	निदर्श द्वारा ऋणप्राप्ति	प्रतिशत
बैंक व सहकारी संस्था	125	47.16
नियोक्ता	30	11.32
साहूकार	60	22.64
मित्र व रिश्तेदार	50	18.86
योग	265	100.00

तालिका–8
भविष्य मैं खेती को अपनाये जाने के संबंध मैं निदर्श का दृष्टिकोण

कृषि का कार्य ही करेंगे	कृषि का कार्य प्राथमिकता से नहीं करेंगे।	योग
156	109	265
58.90 प्रतिशत	41.10 प्रतिशत	100 प्रतिशत

उक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि कृषक वर्ग मैं कृषि नवाचारों की प्रवृत्ति अधिक मात्रा मैं नहीं है क्योंकि चयनित वर्ग मैं शिक्षा का स्तर भी अधिक नहीं है। यही कारण है कि सरकारी संस्थानों से प्राप्त ऋण आदि की सुविधाओं का लाभ निर्देश के औसत व्यक्तियों को प्राप्त नहीं हो पाता। निदर्श मैं ज्यादा संवर्ग सीमांत व छोटे कृषकों का है जो भविष्य मैं खेती को ही व्यवसाय के रूप मैं अपनाने के पक्ष मैं नहीं है। दरअसल भारतीय आम कृषक उत्पादन के समय अनाज का भंडारण नहीं कर पाता और तुरंत उत्पादित अनाज को बेच देता है। बदले मैं खुदरा समय–समय पर खरीदता है। जब वह बेचता है तो मूल्य कम होते हैं। लेकिन जब खरीदता है तब मूल्य बढ़ जाते हैं। ऊँची ब्याज दरों पर निजी स्तर पर प्राप्त किया गया ऋण किसान को आत्महत्या जैसे कार्य के लिये विवश कर देता है। निरंतर गिरता भूजल स्तर व भूमि की उर्वराशक्ति कम होना आधुनिक तकनीकों का कम इस्तेमाल आदि अनेक अन्य ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से खेती लाभ का व्यवसाय नहीं रही। इस संबंध मैं निम्नलिखित सुझाव दिये जा सकते हैं :–

सुझाव– 1. खाद्य प्रसंस्करण व संशोधन की इकाईयों का स्थानीय स्तर पर विकास किया जाना चाहिये। 2. एकाधिक कृषि फसलों के उत्पादन व गुणवत्ता मैं सुधार के लिये कृषि अनुसंधान कार्य व प्रशिक्षण की सुविधा कृषकों को मुहैया कराई जाये। 3. नवाचारों का प्रयोग, जैविक खेती आदि के माध्यम से खेती को सत् विकास का आधार बनाये। 4. सिंचाई सुविध ााओं को बढ़ावा देना चाहिये। 5. किसानों के उत्पाद का समर्थन मूल्य बढ़ाया जाये। 6. गैर फसल आधारित कृशि भी महत्वपूर्ण है। दीर्घकालिक विकास के लिये यदि व्यावसायिक दृष्टिकोण से काम किया जाये तो पशुपालन के साथ हॉर्टिकल्चर के जरिये भी उच्च विकास दर प्राप्त की जा सकती है। 7. जिस प्रकार (SEZ) उद्योगों के लिये निर्धारित किये जा रहे हैं वैसे ही विशिष्ट कृषि क्षेत्र निर्धारित किये जायें।

संदर्भ

1. "भारत मैं विकास की चुनौतियाँ",
मानचन्द खण्डेला, आविष्कार पब्लिशर्स डिस्ट्रीब्यूटर, जयपुर (राज.), प्रथम संस्करण 2007.
2. वाय.के. अलग (ई.डी.) 2003, "Globalization and Agriculture Crisis in India',
Mukharjee, Tanushree and Chatoki Pal, Globalisation and Crisis in Indian Agriculture. Deep and Deep Publication, New Delhi.
3- "Economical and Political Weekly'
Agriculture IndebtedneSaas : Crisis and Revival Balasaheb Vikhe Patil, February 2008.
4- "Third Concept'
Globalization and Agriculture, Sharda Prasad,
Dec. 2005.
5. कुरूक्षेत्र –
   1. किसानों की बदहाली तथा समाधान के उपाय, वंदना मिश्रा, सितम्बर 07.
   2. हरित क्रांति मैं भुखमरी : भरत दुबे, जुलाई 2008
   3. भारत के आर्थिक विकास मैं कृषि की भूमिका : अनिल प्रताप सिंह, अगस्त 07.
6- "Down to Earth' - (1-15 Oct. 08) Farming made unprofitable.